दि. 20.7.99

सेवामें,

उपसचिव (ओ. एण्ड एम.)
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग,
नई दिल्ली ।

विषय : शिक्षा विभाग में नीतिगत परिवर्तन हेतु एक सुझाव

संदर्भ : प्रशासनिक सुधारों हेतु सरकारी विज्ञापन (जुलाई 99)

मान्यवर,

निवेदन है कि राजस्थान सहित अधिकांश राज्यों में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार कन्या महाविद्यालय खोले जा रहे हैं । तहसील तथा खण्ड स्तर के कस्बों में खुल रहे इन महाविद्यालयों में मात्र 100-400 बालिकाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं जबकि सहशिक्षा के महाविद्यालयों में 3000-5000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । मूल प्रश्न यह है कि कन्या महाविद्यालय खोल देने से किसी भी क्षेत्र की उच्च शिक्षा की समस्या समाप्त नहीं होती हैं बल्कि असमानता का प्रसार होता है तथा प्रशासनिक व्यय बढ़ता है। राजस्थान में विगत 5 वर्ष में 30 कन्या महाविद्यालय खोले गए हैं जबकि सहशिक्षा के मात्र 6 कालेज खोले गए हैं ।

मान्यवर, समाज एवं परिवार में लड़का-लड़की एक साथ रहते हैं, स्कूलों में एक साथ पढ़ते हैं, शिक्षाप्राप्ति के पश्चात नौकरी एक साथ करनी है तथा विवाहोपरांत एक साथ जीवन भी बिताना है तो महाविद्यालयी शिक्षा के समय हम किशोरियों तथा युवतियों को लड़कों से पृथक न रख कर शिक्षा क्यों दे रहे हैं? चूंकि महिला शिक्षा के विकास के नाम से पृथक से बजट मिलता है अतः कन्या महाविद्यालय खोले जा रहे हैं ।

मेरा सुझाव है कि उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु सभी महाविद्यालय सहशिक्षा के हों ताकि प्रशासनिक व्यय भी कम हो तथा महाविद्यालयों के उद्देश्य भी पूरे हों, साथ ही महिला पुरुष समानता की नींव अधिक मजबूत हो ।

सादर

भवदीय

S. Kataria

(डॉ. सुरेन्द्र कटारिया)
पोस्ट बॉक्स नं. 20
सीकर - 332001 राज.

Scanned with OKEN Scanner